SHRI DRUPAD BORGOHAIN: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the Ministry has taken a decision to convert Dhodar Ali Road of Assam into a national highway after getting various memoranda. Can it be made as the N.H. No. 28, as already 27 National Highways are there and you can add one more?

MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI: Sir, I will be very happy to keep on adding the State Highways as National Highways, but just as a matter of information, we have today the demand pending for conversion of about 42,000 kms. of State Highways into National Highways. During the first 50 years of independence, we added about 13,000 kms., but in the last four or five years, we have added another about 24,000 kms. Therefore, at the moment, it is not possible to take up conversion of State Highways into National Highways because of financial reasons and fo take up the work of conversion on one highway, we need Rs. 1.25 crores per year. At the moment, because of financial constraints, we are not in a position to do this. But, as and when this thing is done, I am sure, all priority areas will be included.

Procurement of rice from Orissa

*243. SHRI SURENDRA LATH: Will the Minister of CONSUMER AFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government have taken steps to procure rice from various states;

(b) the target of procurement set for the year 2003-04, State-wise; and

(c) the quantum of rice proposed to be procured from Orissa?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SUBHASH MAHARIA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) The State-wise estimates for the procurement of rice during Kharif Marketing Season 2003-04 are given in the Statement-I (*See* below)

(c) An estimated 2.00 lakh tonnes of paddy and 12.00 lakh tonnes of levy rice is estimated to be procured in Orissa during Kharif Marketing Season 2003-04.

Statement-I

Estimates for procurement of rice in States during kms 2003-04

(Quantity in lakh tonnes)

STATE	RICE*
Madhya Pradesh	2.75
Chhatisgarh	19.00
Bihar	2.00
West Bengal	10.00
Maharashtra	2.50
Punjab	80.40
Assam	0.10
Haryana	18.50
U.P.	16.00
Orissa	13.00
Uttaranchal	4.00
Jharkhand	0.10
Nagaland	0.05
Rajasthan	0.50
Andhra Pradesh	50.00
A & N Islands	0.10
Tamil Nadu	1.00
TOTAL:	220.00

*Includes paddy in terms of rice.

SHRI SURENDER LATH: Sir, the hon. Minister has stated in his reply that the estimated target of procurement of paddy in Orissa is 2 lakh tonnes. Sir, Orissa is a paddy-producing State and, fortunately, this year, there is a bumper crop of paddy there. I want to know from the hon.

Minister as to whether the Government is considering to increase the procurement target of paddy from 2 lakh tonnes to 5 lakh tonnes directly from the farmers.

श्री सुभाष महरिया: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने उड़ीसा के बारे में जानना चाहा है कि उड़ीसा के लिए जो चावल की खरीद है, उसके लिए क्या लक्ष्य रखे गए हैं? भारत सरकार की ओपन एंडड पॉलिसी के तहत उड़ीसा के लिए 2.00 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। मुझे माननीय सदस्य को यह बताते हुए खुशी है कि इस बार एफ.सी.आई. ने खरीद के लिए 20 सेंटर्स से बढ़ाकर 40 सेंटर्स एप्रूव किए हैं जो चालू हो चुके हैं। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि एफ.सी.आई. ने रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट सम्बलपुर, बारगढ़ और झांसागुड़ा में 15 सेंटर्स खोले हैं। तीतलागढ़ के बोलंगीर, सोनपुर, कालाहांडी और नावापाडा के लिए 17 सेंटर्स खोले गए हैं। इसी प्रकार से जयपुरे के लिए कोरापुट, अवाई नवरंगपुर, मल्कानगिरि और रायगौड़ा के लिए भी 8 सेंटर्स खोले गए हैं। मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी भी देना चाहूंगा कि खरीफ के लिए भारत सरकार की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में एफ.सी.आई. और डीसेन्ट्रलाइजेशन के तहत उड़ीसा को सातवें राज्य के रूप में शामिल कर लिया गया है और इसी महीने 8 दिसंबर को उड़ीसा के साथ एक एम. ओ.यू. साइन हुआ है, जिसके तहत उड़ीसा भी डीसेन्ट्रलाइजेशन के तहत अपनी खरीद करेगा। इसलिए उड़ीसा में जो अच्छी आवक है, उसकी खरीद की जाएगी।

SHRI SURENDRA LATH: Sir, there are a large number of complaints in the form of FAQ in respect of purchase of paddy from farmers. In the last Kharif season, a large part of the crop had been damaged due to untimely rains and floods in Orissa. Under the uniform specifications of FAQ, what is the maximum limit of damage, in the form of discolouring and sprouting etc. that is allowed under the relaxed specifications? What is the percentage? Sir, I would also like to know whether the Government would enhance the relaxation in the specifications of FAQ in the interest of farmers in Orissa.

श्री सुभाष महरिया: सभापति महोदय, मुझे माननीय सदस्य को यह बताते हुए खुशी है कि क्षतिग्रस्त, रंगहीन, अंकुरित और घुन लगा हुआ जो चावल है, उसकी जो 3 परसेंट तक की खरीद थी, उसको रिलैक्स करते हुए 5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार से टूटे हुए दाने और सिकुड़े हुए दाने की जो 3 प्रतिशत तक कर खरीद होती थी, उसको बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार से रॉ राईस के लिए जो आउट टर्न रेशो 67 परसेंट और 68 परसेंट था उसको रिलेक्स करके 65 परसेंट और 66 परसेंट कर दिया गया है। साथ ही एफ.सी.आई द्वारा लेवी के लिए जो 14 लाख टन चावल लिया जाएगा, उसको प्रोक्योर करने के लिए 13 लाख टन एफ. सी. आई.

खरीद करेगा और एक लाख टन वहां कि स्टेट गवर्नमेंट खरीद करेगी। इस प्रकार से खरीफ की फसल की जो खरीद होने वाली है, किसान के हित में उसके रिलैक्सेशन को बढ़ा दिया गया है।

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: Sir, I want to know whether it is a fact that the policy to which the Minister has just now referred is not actually the policy; it was done only on the appeal of Orissa farmers, who had gone to the court and the court had given the order that the FCI and the State Government should directly purchase rice from the farmers. After that, the forty centres, which have been opened now, are not enough for the total purchase of rice from Orissa farmers.

Secondly, I want to know whether it is a fact that in the name of this levy rice and paddy procurement, mill-owners are actually harassing the farmers. Only the BPL/APL rice is being recycled; the mill-owners are not actually purchasing any paddy from the farmers and, consequenlty, the Orissa farmers are being harassed.

उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री शरद यादव: सभापति जी, माननीय खूंटिआ जी ने जो बात कही है, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि एफ.सी.आई. जो खरीद कर रही है, वह इस साल ही नहीं कर रही है, पिछले बरस भी उसने खरीद की थी। आपकी यह बात सही है कि वहां 2 साल पहले वहां की जो अदालत है, वहां की जो हाईकोर्ट है, उन्होंने आदेश दिया था कि राज्य सरकार खरीद करे और राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। निश्चित तौर पर राज्य सरकार गई थी। लेकिन पिछले साल में भी एफ.सी.आई. को 20 सेंटर खोलने थे। लेकिन खूंटिया जो ठीक कह रहे हैं कि 505 टन पर खरीदा गया। वहां बहुत ठीक नहीं था। इसलिए मैंने दौरा भी किया। उन्होंने रिलेक्सेशन नहीं दिया था। वहां जाकर रिलेक्सेशन दिया। लेकिन इस बार हमने स्टेट गवर्नमेंट के साथ एम.ओ.यू. साइन किया है कि वे लोग भी खरीद करें। लेकिन हमने 20 से 40 सेंटर खोले हैं। रिलेक्सेशन पहले दे दिया और इस समय तक तीन हजार नौ सौ टन खरीद प्रोक्योरमेंट हो चुकी है। कई सेंटर खुल गए हैं और कई सेंटर खुलने वाले हैं। सभापति जी, निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि उड़ीसा, बिहार, असम जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं ....(व्यवधान) राजस्थान का तो हम खरीद चुके हैं। वहां बाजरा और मक्का की खरीद थी। वहां उसको हमने किया है। मैं खूटिआ जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इस बार 20 की जगह 40 लिए हैं और इस बार पूरी तैयारी कर रहे हैं। जो कमजोर इलाका है, जो गरीब इलाका है उनमें एफ.सी.आई. अपनी पूरी ताकत लगा रही है।

श्री सभापति: ठीक है, आप पूरी तैयारी कीजिए।

SHRI B.J. PANDA: Sir, my supplementary relates to the second part of Shri Khuntia's question, which the hon. Minister has not answered, regarding allegations of recycling of rice. There are widespread allegations that the procurement authorities have been involved in collusion with certain mill-owners so that the same quantum of rice is purchased again and again, and no benefit goes to the farmers. My question is, whether the hon. Minister has enquired into this, and what are the reports he has got?

श्री रमा शंकर कौशिक: सर, हमारे यहां भी धान ....(व्यवधान)

श्री सभापति: देखिए, क्वेश्चन के बाद जानकारी आप उन्हें दे सकते हैं, वह जानकारी आप उन्हें दे दीजिए।.....(व्यवधान) Eveything which is said in this House is important. (*Interruptions*) Please take your seat. नहीं-नहीं यह गलत बात है।

SHRI B.J. PANDA: Sir, he has not answered my question. (*Interruptions*)

श्री मूल चन्द मीणा: राजस्थान में बाजरा की खरीद नहीं थी।...(व्यवधान)

डा. अबरार अहमद: लोग बाजरा लेकर भटक रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब कहां बाजरा, कहां चावल। राजस्थान का ध्यान रखो। राजस्थान के आदमी इतने इंटेलीजेंट होते हैं कि बाजरा और चावल को नहीं समझते हैं।...(व्यवधान) नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन, आंसर नहीं आया।

श्री सभापति: आप सुनना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं।...(व्यवधान) तो आप बैठ जाइए।

श्री शरद यादव: सभापति जी, जो पंडा जी ने कहा है मैं उस बात से सहमत हूं कि रिसाइकिल होता है और वहां जो राइस मिलर्स हैं वहां सीधे लेवी सिस्टम से लिया जाता है और अधिकांश चावल जो खरीदता है वह लेवी सिस्टम से होता है। मैं पंडा जी से कहना चाहता हूं कि आज तक वे एम.पी. हैं। मेरे पास तो कहीं भी रिसाइकिल की कम्पलेंट आए, यह जरूर है कि यह होता है और वहां जो राइस मिलर्स हैं उनकी लॉबी इतनी मजबूत है कि मैं बयान नहीं करना चाहता समय भी नहीं है और अगर उसकी डिबेट भी हो जाए तो अच्छा होगा। अगर कोई चीज हो तो उसको पकड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। रहा सवाल जो कौशिक जी ने पूछा है ...(व्यवधान)

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन्, एक छोटा सा सवाल है।

श्री सभापति: नहीं।